आकाशवाणी

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शनिवार 10.01.2026 समय 0720

मुख्य समाचार :-

* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति दी।

* न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

* मुख्य सचिव ने लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना से जुड़े कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

* अल्मोड़ा में एस्ट्रो टूरिज्म पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

सीबीआई कार्रवाई

उत्तराखण्ड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। यह निर्णय अंकिता के माता-पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है, जिसे इस पूरे प्रकरण में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य पूरे मामले में शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने दोहराया कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वह पूरी दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

गौरतलब है कि साल 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत गंभीर कार्रवाई की। महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई तथा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और मजबूत पैरवी के चलते उन्हें जमानत नहीं मिली। जांच पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल हुई और निचली अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शपथ

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उन्हें दोपहर दो बजे देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 जनवरी को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

समीक्षा

मुख्य सचिव ने सचिवालय में लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने को कहा गया और मुख्य सचिव ने परियोजना से जुड़े कार्यों की विस्तृत प्रगति की जानकारी ली।

बैठक में परियोजना से संबंधित सभी ड्रॉइंग्स को समय पर तैयार कराने और केंद्रीय जल आयोग से उनका पुनरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए चरणबद्ध टाइमलाइन और प्रगति चार्ट तैयार करने, दक्ष मानव संसाधन, मशीनरी और निर्माण

सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हाइड्रो मैकेनिकल ड्रॉइंग्स शीघ्र उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव, ऊर्जा को अपने स्तर पर लखवाड़े में कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के तहत प्रस्तावित बांध 204 मीटर ऊंचा होगा, जिसकी लाइव स्टोरेज क्षमता 330 दशमलव चार मिलियन क्यूबिक मीटर-एमसीएम है और इससे 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी।

एस्ट्रो टूरिज्म प्रशिक्षण कार्यशाला

अल्मोड़ा में खगोल विज्ञान और पर्यटन (एस्ट्रो टूरिज्म) पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 15 दिवसीय कार्यशाला में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग और अल्मोड़ा के 30 से अधिक छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल की मास्टर ट्रेनर श्वेता ध्यानी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य पर्यटन को एस्ट्रो टूरिज्म से जोड़ते हुए कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र धामी ने बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान और पर्यटन पर आधारित यह कार्यशाला छात्र-छात्राओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षुओं ने बताया कि कार्यशाला में खगोल से जुड़ी कई जानकारियां बताई और दिखाई जा रही हैं।

20 जनवरी तक चलने वाली एस्ट्रो टूरिज्म प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को टेलीस्कोप संचालन, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा रात में आकाशीय पिंडों के अवलोकन का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जा रहा है।

सांसद खेल महोत्सव

देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल व राजपुर विधायक खजानदास ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से फिट, अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

सांसद डा. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य गांव-गांव की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है।

गौरतलब है कि सांसद खेल महोत्सव के अन्तर्गत वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, पिट्ठू, एथलेटिक्स व अन्य जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ब्लॉक स्तर की विजेता टीमों ने भाग लिया।

सूचना का अधिकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन का मजबूत आधार है। कल सचिवालय में आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून ने नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार दिया है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया भी आसान हुई है। उन्होंने प्रत्येक विभाग से उन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करने को कहा जिनकी बार-बार मांग की जाती है, जिससे नागरिकों को स्वतः जानकारी मिल सके और पारदर्शिता बढ़े।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया।

जन-जन की सरकार, जन के द्वार

जन-जन की सरकार, जन के द्वार अभियान के तहत पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड रिखणीखाल की चुरानी न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 17 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत 260 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित भी किया गया।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर—

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है—बिटिया के माता-पिता की भावनाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने लिया फैसला।

सूचना का अधिकार जन सशक्तिकरण और पारदर्शी शासन का मजबूत आधार शीर्षक से अमर उजाला लिखता है—सूचना आयोग को प्राप्त हुए 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन, बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान।

दून अस्पताल में 'स्कैन एंड शेयर' ने बदली ओपीडी की तस्वीर–इस शीर्षक से दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार 650 ने डिजिटल माध्यम से किया पंजीकरण, मरीजों ने डिजिटल पर्ची बनाकर लंबी लाइन से पाई मुक्ति।